[Shri B. R. Bhagat]

Birla-K. P. Goenka and other I. J. M. A. manufacturers had connered B. Twill bags and had held them Benami in anticipation of decontrol. In his second letter of 10th March, 1969, to the Deputy Prime Minister a copy of which was again not endorsed to me, he had stated that mills held about 55,000 bales benami or otherwise. These letters, therefore, cannot be deemed to affect the correctness of the answer given in the House on 19.3.1969.

7, Shri Madhu Limay has again referred to transactions in B. Twill bags at prices higher than the controlled price and has asked for an enquiry to find out whether the additional income has been properly assessed and taxed. Since this matter concerns the Ministry of Finance, they will, no doubt. be looking into it.

8 I regret to state that the allegations made by Shri Madhu Limaye are without any basis. Government had taken the decision not to decontrol B. Twills even before this question was raised by him. There was no occasion whatsoever for considering the payment of a price higher than the controlled price for purchase of B. Twills to meet the requirments of the D. G. S. &. D. The industry has expressed its willingness to cooperate with the Government to meet the requirements of B. Twill bags within the controlled price, and it is expected that the arrangements will soon be finalised. In these circumstances, the statement made by Shri Madhu Limaye is unwarranted and is based on wrong assumptions.

MOTION *RE* : SUSPENSION OF PART OF CLAUSE (C) OF RULE 110 IN RELATION TO CONSTITUTION (TWENTY-SECOND AMENDMENT) BILL.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : I move.

> "That clause (c) of the rule 110 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for withdrawl of the Constitution (Twenty-second Amendment) Bill, 1968, as reported by the Joint Committee, be suspended in so far as that clause requires inclusion of additional provisions in the Bill to replace the said Constitution (Twenty-second Amendment) Bill, 1968. "

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने रूल 110 के ससपेंशन के बारे में कहा है। धारा 388 के तहत वह ससपेंशन करना चाहते हैं। मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि इस में जो सब से जरूरी बात है वह यह है कि इस में कसेंट आफ दी स्पीकर इसके लिए जरूरी होती है। उसके बाद अगर हाउस एडाप्ट करेगा तब यह रूल ससपेंड होगा, वर्ना नहीं होगा।

MR. SPEAKER : Let me say one thing. All these aspects were discussed yesterday in the Business Advisory Committee. Normally, the same Bill is not introduced in the same session. Never has it been done. I was told that when Panditji was alive, when the Constitution (Amendment) Bill was defeated, a special session was called for that. That was a tragic session when unfortunately we lost him for ever. So, when he was alive, a special session was called to have the Constitution (Amendment) Bill again introduced. But in view of the urgency, this was suggested. Yesterday, in the Bussiness Advisory Committee meeting, Mr. Ranga was also there and others was also there. It was said that this should not become a precedent. You cannot bring it everytime, but this is done as a special case in view of the importance of the Hill Districts in Assam; it was therefore suggested that this may be specially permitted, but that it should not be repeated. This is what the Bussiness Advisory Committee decided. In view of that, I thought my leave could be given. You need not read the rules. All of them were read there, and it is only after that, that the Business Advisory Committee asked me to give leave so that as a special case it may be done. So, do not take much time.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : विजिनैस एडवाइज़री कमेटी में कौन सी अर्जेंसी आपके सामने इन्होंने रखी है, इसकी जानकारी हम को नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह जो अर्जेंसी आप कह रहे हैं उसको सदन में बताया जाए। क्यों आप इस एक विशेष निर्णय को करने जा रहे हैं ? मैं समझता हूं कि अगर इस सदन के नियम इसी तरह से रोज़ रोज़ स्थगित किये जाने लगे तो एक दिन इस संसद का महत्व सर्वथा समाप्त हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि जो अर्जेंसी विजिनेस एडवाइज़री कमेटी में बताई गई है उसको सदन में भी बताया जाए।

MR. SPEAKER : You can reject it. Ultimately is that of this House. It is not as thought it is accepted immediately when it is admitted here. That is why he is making the motion before the House that leave be given. If the House does not give leave. he cannot have the leave. Therefore, it is not as thought it is already given the leave. It is before the House. It may be rcjected outright; Shri Prakash Vir Shastri has the right to reject it and the whole House has the rigt to reject it. It is only placed before the House now.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा अभिप्राय यह है कि जिस कनवेंशन का आपने उल्लेख किया है और जवाहर लाल नेहरू ने जिस महान पम्परा को स्थापना की थी, उस परम्परा को क्यों तोड़ा जा रहा है।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज़ यह है कि आपने जो इसके लिए परमिशन दी है, उस पर मुझे आप से एक प्रार्थना करनी है–

MR. SPEAKER : You cannot question that now. I would not allow you to question that. The Speaker has permitted it and then it is placed before the House. You cannot question that. I take serious notice of it if you question that. After cosulting the Business Advisory Committee in which your party was also represented and in which Shri Ranga was also pre:ent, this was done.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : They have not objected to this in the Business Advisory Committee.

SHRI KANWAR LAL GUPTA ; I am the last person to question your ruling, Sir. But I have a right to make a request to you.

मेरा कहना यह है कि यह एक बहुत ही डेंजरस प्रेसीडेंट होगा। आपने अभी कहा है कि कनवेंशन यह था कि इस प्रकार से अगर कोई बिल रह जाता है तो स्पेशल सैशन होना चाहिए या अगले सैशन में उसको लाया जाना चाहिये। मैं नहीं समझता हूं कि इसके बारे में कोई अर्जेंसी है। मैं यह समझता हूं कि यह बिल फ्लड गेट खोलेगा और इससे देश को सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को बल मिलेगा, वे पनपेंगी और सीड्स आफ डिसइंटेग्रेशन पैदा होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग हमारी पार्टी की जो राय है उससे सहमत न हों। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस में कोई अर्जेंसी नहीं है। गवर्नमेंट मैजोरिटी मोबलाइज़ नहीं कर सकी है तो क्या उसको अपनी इस इनएफिशेंसी के लिए या लैक आफ मोबिलिटी के लिए रिवार्ड मिलना चाहिये ? क्या उसकी खातिर इस रूल को ससपैंड किया जाना चाहिये ? उनकी इनएफिशेंसी की उनको पैनेलटी होनी चाहिये, रिवार्ड नहीं होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि यह प्रेसीडेंट नहीं बनेगा। अगर यह साधारण बात होती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन यह संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। अगर यह युनेनिमस भी होता तब भी कोई बात थी। लेकिन हमारी पार्टी इसकी मुखालिफत करना चाहती है। हम नहीं चाहते हैं कि यह बिल पास हो क्योंकि हमारे खयाल

[श्री कंवर लाल गुप्त]

से यह देश की यूनिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा ।

वैसे तो मैं इसको अपोज़ करूंगा । हाउस चाहे तो हमारी आपत्ति को रद्द कर सकता है और उनको इसकी इजाज़त दे सकता है । लेकिन मुझे यह कहना है कि जब तक युनैनिमिटी न हो हाउस की सभी पार्टीज की, तब तक कृपा करके आप अपनी कंसेंट न दिया करें इसका कारण यह है कि यह डेंजरस प्रेसीडेंट होगा और इस डेंजरस प्रेसीडेंट को आइंदा सरकार मिसयूज करेगी ।

SHRI S. M. BANERJI (Kanpur) : As a member of the Business Advisory Committee and as the representative of my group, I gave my full suprort to the withdrawal of this Bill and introduction of the now Bill, respecting the sentiments of the Hill people. They though it would be passed that day itself.

When we agreed to this suggestion, the Minister of Parliamentary Affairs also was present and member expressed the view that on that day, after the Bill fell through, a sense of regret should have been shown by the treasury benches. We expected some words of regret, but they did not do it. We do not expect the Prime Minister to express regret to foreign countries, but to our own Parliament, which you as the custodian, she can express regret. If a lady cannot express regret, let some gent there express regret,

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा निवेदन यह है कि आपकी जिम्मेवारी केवल इतनी नहीं है कि सदन में आप व्यवस्था बनाये रखें । आपकी यह भी जिम्मेवारी है कि सदन के गौरव की आप रक्षा करें । अभी स्वयं आपने एक घटना का उल्लेख किया है कि किस प्रकार से जवाहर लाल नेहरू जी के समय में जब इस प्रकार की एक घटना हुई थी तब उन्होंने दुबारा विशेष अधिवेशन बुलाया था और उस अधिवेशन में उस विधेयक को उपस्थित किया था । उससे पहले वाले अधिवेशन में नहीं किया था । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्री यशवन्त राव चव्हाण या बिजिनैस एडवाइज़री कमेटी से हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं पहुंच सकी है जिससे पता चले कि इसमें क्या अर्जेंसी वाली बात है । एक छोटे से प्रदेश को यदि इतनी जल्दी पृथक नहीं किया जाता है तो कौन सी मुसीबत आने वाली है, कौन सी भारत पर भयंकर घटना घटने वाली है यह नही बताया गया है । मेरी समझ में नही आ रहा है कि क्यों इस प्रकार की अस्वस्थ परम्परा को प्रारम्भ किया जा रहा है । कल आपको याद होगा जब तेलंगाना के मामले पर बहस हो रही थी तो यह कहा गया था कि जिस प्रकार से असम के अन्दर एक अलग हिल स्टेट बनाई जा रही हैं उसी तरह से तेलगाना के अन्दर भी किया जा सकता है । अब जो गृह मन्त्री महोदय कर वाने जा रहे हैं उससे इस प्रकार की घटनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा । इसलिए मैं चाहता हूँ कि शान्ति के साथ इस बात पर विचार किया जाए और इस अधिवेशन में इसको उपस्थित न किया जाए ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, असम बिल को जल्द से जल्द पास किया जाए यह मेरी भी राय है । लेकिन मुझे उन बातों को ले कर आपत्ति है जि जिस दिन खंड दो के उपर विभाजन हुआ था और आपने घोषणा की थी कि वह गिर गई है तो उसके बाद मन्त्री महोदय इतने गड़बड़ा गए और उलझ गए कि जो सही कारंवाई उनको करनी चाहिये थी वह उन्होंने नहीं की । उस दिन अन्त में आपने कहा कि वह वापिस ले रहे हैं और आप दूसरी आइटम पर चले गए। लेकिन सदन की कार्रवाई को जिन्होंने पढ़ा है—

MR. SPEAKER : The Home Minister announced it.

श्री मधु लिमये : नहीं किया, इसलिये मैं उन्हीं की नुक्ताचीनी कर रहा हूं। मै कह रहा हूँ कि उनके सामने कई रास्ते थे। सब से पहले यह रास्ता था" अगर वह गड़बड़ा नहीं जाते''' कि वह धारा 109 का सहारा लेते। इस धारा का हम लोग भी अपनी बातों को उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुरन्त इनको प्रस्ताव करना चाहिये था इस धारा के अन्तर्गत। इस में आप देखें कि क्या कहा गया है। आइंदा के लिए भी अगर आप ध्यान में इसको रखेंगे तो अच्छा होगा। इस में कहा गया है :

> "At any stage of a Bill which is under discussion in the House, a motion that the debate on the Bill be adjourned may be moved with the consent Speaker."

तुरन्त उनको चर्चा स्थगित रखने का प्रस्ताव करना चाहिये था।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : That clause was defeated.

श्री मधु लिमये : उससे कोई इन्कार नहीं करता। लेकिन उनको प्रस्ताव देना चाहिये था स्थगन का। जहां तक वापसी का सवाल है मेरी अपनी राय है कि इस नियम को स्थगित रखने की कोई जरूरत नहीं है। मन्त्री महोदय नियम 110 को देखें। उस में कहा गया है कि इस बिल में अगर कोई आप परिवर्तन कर के इस को पेश करेंगे या उसमें कोई नई बात जोड़ेंगे तो इस नियम को स्थगित करने की कोई जरूरत नहीं है। कल यहां पर तेलंगाना पर बहस हुई थी। तब मैंने सुझाव दिया था कि अलगाव और पृथकता के लिए तो आप आसानी से सारा काम कर सकते हैं।

13 hrs.

लेकिन वर्तमान राज्यों को बचाने के लिये अगर प्रादेशिक स्वायत्तता की बात आपको करनी है तो आप कहते हैं कि संविधान में परिवर्तन करना चाहिये। जब आसाम को ले कर आप कर ही रहे हैं तो आप कैबिनेट की बैठक बुलाइये, दूसरे विरोधी दलों के नेताओं से बातचीत करिये और इस विधेयक में एक नई धारा जोड़े जिससे आपके हाथ में अधिकार होंगे–प्रादेशिक स्वायत्तता दिलाने के। इसका नतीजा क्या होगा–110 नियम को स्थगित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संविधान में बार बार संशोधन नहीं लाना पड़ेगा और राज्यों की एकता बनी रहेगी। आप इस सुझाव पर विचार करें।

SHRI M. R, MASANI (Rajkot) : Mr. Speaker, Sir, we too share the reluctance of many Member of this hon. House to waive the rules too lightly and to create precedents which may be undesirble in the future. In a similar situation, I think it was in1964,I remember we strongly opposed the idea of bringing an amendment to the Constitution, which had been rejected, for a second time in the same session. So we are not lacking in the sense of feelings that some hon. Member have expressed. But in this particular case we believe that there are broad considerations of the national interest that require that what has happened should be undone as fast as possible. This is not the time to go into the merits of the matter and I do not want to indicate now what those considerations are. But we feel a sense of urgency and it was that which led the Business Advisory Committee to develop a consensus that this should be done. If I may say so, Sir, with all respect, you have only done your duty by the House in giving your sanction. we shall, therefore, support the motion. But I think the Leader of the House owes an appropriate word to the House about the inconvenience caused to Parliament and also an assurance that they will not lightly invite the House again to restort to this exception which we are making in this case.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay--Central) : Sir, with regard to rule 388, firstly there is the importance of the rule and then there is a convention. That con-

[Shri R. D. Bhandare]

vention has been followed. But the very fact there is a rule which can meet an emergency shows that the rule could be taken advantage of (*Interruption*). Since Shri Limaye has referred to rule 109 and 110, if we are to read both the rule--109 and 110--then the Government would have been in difficulty and it would not have been possible for them to take advantage of rule 109 and 110 together because rule 110 specifically speaks what should be done if the Bill is withdrawn. Therefore, the rule ought to be suspended.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : I have no hesitation expressing my regret for the inconvenience caused to hon. Members and I think we will see in future that this sort of thing does not happen.

MR. SPEAKER : The question is :

"That clause (c) of the rule 110 of the Rules of procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for withdrawal of the Constitution (Twenty-second Amendment) Bill, 1968, as reported by the Joint Committee, be suspended in so for as that clause requires inclusion of additional provisions in the Bill to replace the said Constitution (Twenty-second Amendment) bill, 1968. "

The motion was aodpted.

13.03½hrs

CONSTITUTION (TWENTY-SECOND AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : Sir, I beg to move for leave to withdraw the Constitution (Twenty-second Amendment) Bill, 1968 as reported by the Joint Committee which is pending in the Lok Sabha.

MR. SPEAKER : The Question is :

"That leave be granted to withdraw the Constitution (Twenty-second Amendment) Bill, 1968 as reported by the Joint Committee, which is pending in the Lok Sabha. "

The motion was adopted.

SHRI Y. B. CHAVAN : Sir, I withdraw the Bill.

14.04hrs. *

DEMANDS FOR GRANTS--*Contd.*

Ministry of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs.

MR. SPEAKER : The House will not take up discussion and voting on Demands Nos. 58 to 61 and 121 relating to the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs for which 6 hours have been allotted.

Hon. Members present in the House who are desirous of moving their cut motions may send slips to the Table by 14.15 hours indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. They will be treated as moved if they are otherwise admissible.

We will conclude the discussion and voting on these Demands by about 14.30 tomorrow and then take up the Demands relating to the Ministry of External Affairs.

Demand No. 58- Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs.

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That a sum not exceeding Rs. 72,43,000 be granted to the President *to complete the*

---

* Moved with the recommendation of the President.